



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2294]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 23, 2012/अग्रहायण 2, 1934

No. 2294]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 23, 2012/AGRAHAYANA 2, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

(आयकर)

का.आ. 2777(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80गगछ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राजीव गांधी साधारण बचत स्कीम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये स्कीम आय-कर अधिनियम की धारा 80गगछ की उपधारा (1) के अधीन पात्र प्रतिभूतियों में विनिधान के खाते के लिए किसी पूर्व वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय की गणना में दावा की गई कटौती के लिए लागू होगी।

2. स्कीम का उद्देश्य, - स्कीम का उद्देश्य घरेलू पूंजी बाजार में छोटे निवेशकों की बचतों को प्रोत्साहित करना है।

2. परिभाषाएं - इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(i) “अधिनियम” से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ii) “डी-मैट खाता” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा अधिकथित मार्गनिर्देशों के अनुसरण में भागीदार निक्षेपागार में खोला गया कोई खाता अभिप्रेत है;

- (iii) “निक्षेपागार” से निक्षेपागार अधिनियम 1996 (1996 का 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) में यथा परिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है;
- (iv) “भागीदार निक्षेपागार” से निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (छ) में यथा परिभाषित कोई भागीदार अभिप्रेत है;
- (v) “पात्र प्रतिभूतियाँ” से निम्नलिखित कोई अभिप्रेत है :-
- (क) साधारण शेयर, क्रय की तारीख पर, यथास्थिति, बाम्बे स्टाक एक्सचेंज या नेशनल स्टाक एक्सचेंज द्वारा “बीएसई-100” या “सीएनएक्स-100” के रूप में घोषित साधारण की सूची में आते हैं ;
 - (ख) पब्लिक सेक्टर उद्यमों के साधारण शेयर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा महारत्न, नवरत्न या मिनी रत्न के रूप में वर्गीकृत हैं ;
 - (ग) एक्सचेंज विनिमय व्यापार निधि की यूनितें या राजीव गांधी साधारण बचत स्कीम के साथ पारस्परिक निधि जो उपर्युक्त उपखंड (i) या उपखंड (ii) के रूप में विनिर्दिष्ट हैं, वे किसी स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध और व्यापार होने का और किसी निक्षेपागार क्रिया विधि के माध्यम से उनका समाधान होने का उपबंध है ;
 - (घ) उपर्युक्त उपखंड (i) और उपखंड (ii) के लोक प्रस्ताव के अनुसरण में ;
 - (ङ) उपर्युक्त उपखंड (iii) के नए निधि प्रस्ताव ;
 - (च) किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम के आरंभिक लोक प्रस्ताव जिसमें सरकार की शेयर धारिता इक्यावन प्रतिशत से कम है जो संबंधित पूर्ववर्ती वर्ष में सूचीबद्ध होने के लिए अनुसूचित है और जिसका वार्षिक व्यापारावृत्त प्रत्येक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के प्रत्येक के दौरान चार हजार करोड़ रुपए से कम नहीं है ;
- (vi) “वित्तीय वर्ष” से अप्रैल की 1 तारीख से प्रारंभ और मार्च की 31 वीं तारीख को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ;
- (vii) “प्ररूप” से स्कीम से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;
- (viii) “विनिधान” से स्कीम के अनुसरण में किन्हीं पात्र प्रतिभूतियों में किसी निर्धारिती द्वारा किया गया विनिधान अभिप्रेत है ;

(ix) “नए फुटकर विनिधानकर्ता” से निम्नलिखित निवासी व्यक्ति अभिप्रेत हैं:-

- (क) कोई व्यक्ति जिसने कोई डि-मैट खाता नहीं खोल रखा है और स्कीम की अधिसूचना की तारीख पर व्युत्पन्न खंड में कोई संव्यवहार नहीं किया है ;
- (ख) कोई व्यक्ति जिसने स्कीम की अधिसूचना की तारीख पर कोई डि-मैट खाता खोल रखा है किंतु स्कीम की अधिसूचना की तारीख तक साधारण खंड या व्युत्पन्न खंड में कोई संव्यवहार नहीं किया है.

और कोई व्यक्ति जो किसी विद्यमान संयुक्त डि-मैट खाते में पहला खाता धारक नहीं है, इस योजना के प्रयोजनों के लिए किसी डि-मैट खाते को खोला हुआ नहीं समझा जाएगा ।

- (x) “स्कीम” से राजीव गांधी साधारण बचत स्कीम अभिप्रेत है ;
- (xi) वे शब्द और पद जो इस स्कीम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है और अधिनियम में परिभाषित है उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में समनुदेशित हैं ।

4. पात्रता- स्कीम के अधीन कटौती नए फुटकर विनिधानकर्ताओं को उपलब्ध होगी जो स्कीम की शर्तों का पालन करते हैं और जिनकी वित्तीय वर्ष के लिए सकल कुल आय में जिसमें स्कीम के अधीन किया गया विनिवेश भी है दस लाख रुपए से कम है या उसके समतुल्य है।

5. डी-मैट खाता खोलने के समय प्रक्रिया- नए फुटकर विनिधानकर्ता को किसी डी-मैट खाते को खोलने के समय या अभिहित करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:-

(क) नया फुटकर विनिधानकर्ता स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी नए डी-मैट खाते को खोलने या अपने विद्यमान डी-मैट खाते को अभिहित करेगा ;

(ख) नया फुटकर विनिधानकर्ता भागीदारी निक्षेपागार को प्ररूप क में घोषणा प्रस्तुत करेगा जो नए फुटकर विनिधानकर्ता की प्रारिथिति को सत्यापित करने के लिए निक्षेपागार को उसे भेजेगा ;

(ग) नया फुटकर विनिधानकर्ता राजीव गांधी साधारण बचत स्कीम के पात्र खाते के रूप में यथास्थिति, डी-मैट खाते को खोलते समय या विद्यमान खाते को अभिहित खोलते समय अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) देगा।

6. स्कीम के अधीन विनिवेश के लिए प्रक्रिया - कोई नया फुटकर विनिधानकर्ता निम्नलिखित रीति में स्कीम के अधीन विनिवेश करेगा :-

(क) नया फुटकर विनिधानकर्ता वर्ष के दौरान जिसमें कटौती का दावा किया गया है एक या अधिक संव्यवहार पात्र प्रतिभूतियों में विनिधान कर सकेगा ;

(ख) नया फुटकर विनिधानकर्ता डी-मैट खाते में किसी भी रकम का विनिधान कर सकेगा किंतु स्कीम के अधीन कटौती के लिए पात्र रकम पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ;

(ग) डी-मैट खाते में लाई गई पात्र प्रतिभूतियां नए फुटकर विनिधानकर्ता द्वारा घोषित या अभिहित, पैरा 7 के उपबंधों के अनुसार इसके प्रथम वर्ष के दौरान स्वतः रोध के अधीन होंगी जब तक कि नया फुटकर विनिवेशक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं करता है और ऐसे विनिर्देश के लिए नया फुटकर विनिधानकर्ता प्ररूप ख में घोषणा देगा और ऐसी प्रतिभूतियां उपरोक्त विनिधान की सीमा के भीतर सम्मिलित नहीं होंगी ;

(घ) पचास हजार की अधिकतम विनिवेश सीमा के अधीन रहते हुए, नया फुटकर विनिधानकर्ता पात्र प्रतिभूतियों में वास्तविक रकम के विनिधान में, पहले वित्तीय वर्ष में जिसके संबंध में प्ररूप ख में घोषणा नहीं की गई है अधिनियम की धारा 80 गगछ की उपधारा (1) के अधीन किसी कटौती के लिए पात्र होगा।

(ङ) नया फुटकर विनिधानकर्ता जो किसी निर्धारण वर्ष में अधिनियम की धारा गगछ की उपधारा (1) के अधीन कटौती का दावा करता है किसी पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्ष के लिए स्कीम के अधीन किसी कटौती को अनुज्ञात नहीं होगा ;

(च) नया फुटकर विनिधानकर्ता वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन व्यापारिक दिनों की अवधि के लिए अनुग्रह अवधि को अनुज्ञात होगा जो कि वित्तीय वर्ष की अंतिम व्यापारिक दिवस पर क्रय की गई,

डी-मैट खाते में भी जमा की गई पात्र प्रतिभूतियों के लिए होगा और ऐसी प्रतिभूतियां वित्तीय वर्ष में क्रय की गई समझी जाएंगी ;

(छ) नया फुटकर विनिधानकर्ता डी-मैट खाते में स्कीम के अधीन आने वाली पात्र प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूतियों को भी रख सकेगा जिसके लाभ स्कीम के अधीन प्राप्त हैं ;

(ज) नया फुटकर विनिधानकर्ता स्कीम के अधीन आने वाली पात्र प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूतियों में विनिधान कर सकता है और ऐसे विनिधान स्कीम की शर्तों के धीन नहीं होंगे न ही स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए उनकी गणना की जाएगी ;

(झ) स्कीम के अधीन विनिधान, स्कीम के अधीन आने वाली सभी पात्र प्रतिभूतियों के संगत होगा कि स्कीम के अधीन विनिधानकर्ता द्वारा आरंभिक रूप से लाया गया है या स्कीम के उपबंधों के अनुसार विनिधानकर्ता द्वारा पश्चात्तवर्ती लाया गया है ;

(ञ) दावा की गई कटौती को वापिस लेना होगा यदि विनिधान की अपेक्षा की रोक की अवधि का पालन नहीं होता है या स्कीम की कोई अन्य शर्त का उल्लंघन होता है ।

7. धृति की अवधि की अपेक्षाएं- (1) पात्र प्रतिभूतियों की धृति की अवधि तीन वर्ष होगी जिसकी गणना नीचे दी गई विस्तृत रीति से होगी ।

(2) सभी पात्र प्रतिभूतियां किसी नियत अवधि के लिए धारित होंगी जिसे नियत रोक अवधि कहा जाएगा जो सुसंगत वित्तीय वर्ष में ऐसी प्रतिभूति की क्रय की तारीख से प्रारंभ होगी और पात्र प्रतिभूतियों के अंतिम समूह के क्रय करने की तारीख से एक वर्ष (उसी वित्तीय वर्ष में) पर समाप्त होगी, जिस पर स्कीम के अधीन कटौती के लिए दावा किया गया है ।

(3) नया फुटकर विनिधानकर्ता नियत रोक अवधि के दौरान किसी पात्र प्रतिभूति के विक्रय, बंधक या आडमान के लिए अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) नियत रोक अवधि की समाप्ति के तत्काल पश्चात् प्रारंभ होने की दो वर्ष की अवधि को नमनीय रोक अवधि कहा जाएगा ।

(5) नया फुटकर विनिधानकर्ता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत रोक अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् पात्र प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए अनुज्ञात होगा :-

(क) नया फुटकर विनिधानकर्ता सुनिश्चित करेगा कि स्कीम के अधीन डीमैट खाता नमनीय रोक अवधि के दो वर्ष के दौरान प्रत्येक दो सौ सत्तर दिन की न्यूनतम संचित अवधि के लिए संकलित है जो कि नीचे अधिकथित है :-

(अ) डीमैट खाता पात्र प्रतिभूतियों के विनिधान पत्राधान की जहां मूल्य दिनों की संख्या के लिए संकलन समाधान नमनीय रोक अवधि के भीतर जो अधिनियम की धारा 80 गगछ के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए विनिधान के रूप में दावा की गई रकम के समतुल्य या उच्चतर है, होगा ;

(आ) उपखंड (अ) में किसी बात के होते हुए नमनीय रोक अवधि में पात्र प्रतिभूतियों की बाजारी दर में गिरावट के कारण डीमेट खाते में विनिधान पत्राधान के मूल्य की दशा में,-

- (i) डीमेट खाते में इस अवधि के दौरान कोई ऐसी पात्र प्रतिभूतियां विक्रय की गई हैं, तारीख को नमनीय रोक अवधि के पहले दिन से संकलन विचारण में होंगी ;
- (ii) जहां निर्धारिती उपखंड (आ) में वर्णित पात्र प्रतिभूतियों का विक्रय अपने डीमेट खाते से करता है, वह पात्र प्रतिभूतियों का क्रय करता है और उक्त डीमेट खाता विनिधान पत्राधान का मूल्य तारीख पर, जिसको संकलन होगा -

- (I) अधिनियम की धारा 80गगछ के अधीन कटौती के लिए पात्र के रूप में दावा किए गए विनिधान के कम से कम समतुल्य होगा ; या
- (II) ऐसा विक्रय करने से पहले स्कीम के अधीन विनिधान पत्राधान का मूल्य,

इसमें से जो भी कम हो, होगा ।

(6) स्कीम के अधीन नया फुटकर विनिधानकर्ता का डीमेट खाता विनिधान की धारण अवधि की समाप्ति पर किसी सामान्य डीमेट खाते में स्वतः परिवर्तित हो जाएगा ।

(7) नमनीय रोक अवधि के दौरान विनिधान के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए व्यापार की तारीख के पूर्ववर्ती दिन पर उसका समाप्त मूल्य विचार में लिया जाएगा ।

(8) आरंभिक विनिधान पचास हजार रूपए तक करने के लिए पात्र प्रतिभूतियों की अर्जन की कुल लागत में दलाली प्रभार, प्रतिभूति संव्यवहार कर, स्टॉप ड्यूटी, सेवाकर और सभी कर, जो संविदा टिप्पण में आए हैं, सम्मिलित नहीं होंगे ।

(9) जहां नए फुटकर विनिधानकर्ता के विनिधान का स्वैच्छिक कार्पोरेट कार्रवाई जैसे कंपनियों पर अविलयन, सम्मेलन आदि के परिणामस्वरूप कोई परिवर्तन होता है जिसके परिणामस्वरूप स्कीम के अधीन आने वाली प्रतिभूतियों के अतिशेष या जमा ऐसे विनिधानकर्ता द्वारा दावा की गई कटौती पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा ।

(10) स्वैच्छिक कार्पोरेट कार्रवाई जैसे क्रय द्वारा वापस लेना आदि की दशा में प्रतिभूतियों के अतिशेष में केवल परिणामस्वरूप जहां नया फुटकर विनिधानकर्ता अपना यह विकल्प प्रयोग करता है, स्कीम के प्रयोजनों के लिए किसी विक्रय संव्यवहार के रूप में उसी के समान विचार में लिया जाएगा ।

(11) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इस संबंध में स्कीम के अधीन अनुज्ञात उपपैरा(9) में निर्दिष्ट कार्पोरेट कार्रवाई को अधिसूचित करेगा ।

8. यदि नया फुटकर विनिधानकर्ता स्कीम के किन्हीं उपबंधों को पूर्ण करने में असफल रहता है, किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 80गगछ की उपधारा (1) के अधीन उसे अनुज्ञात मूल्य कटौती, ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष की निर्धारिती की आय को समझा जाएगा और ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कर का दायी होगा ।

9. (1) निक्षेपागार स्कीम के प्रयोजन के लिए डीमेट खाते के रूप में उसका डीमेट खाता अभिहित करने के समय निर्धारिती की नया फुटकर विनिधानकर्ता प्रास्थिति प्रमाणित करेगा ।

4391 G1/12-2

(2) भागीदार निक्षेपागार पात्र प्रतिभूतियों के विनिधान में या डीमेट खाता धारक को डीमेट खाते के माध्यम से व्यापार की किसी वार्षिक विवरणी को देगा ।

10. निक्षेपागार, महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को राजीव गांधी साधारण बचत योजना के सभी लाभार्थियों से प्ररूप ग में यथाविनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक रूप विधान में व्यौरों की समेकित विवरणी संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगा ।

11. पैरा 10 के प्रयोजन के लिए, महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) निक्षेपागारों द्वारा प्ररूप ग में इलैक्ट्रानिक रूप विधान में रिपोर्ट को देने के लिए प्रक्रिया, रूप विधान और मानक अवधारित करेगा ।

12. निर्धारिती सत्यापन के लिए आय-कर से सुसंगत अभिलेखों को, जब कभी अपेक्षित हो, जमा करने के दायी होंगे ।

[अधिसूचना सं. 51/2012-फा. सं. 142/35/2012-टीपीएल]

रमन चोपड़ा, निदेशक (टीपीएल-II)

प्ररूप क

[पैरा 5(ख) देखें]

राजीव गांधी साधारण बचत स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए निक्षेपागार भागीदारी को विनिधानकर्ता द्वारा की जाने वाली घोषणा ।

विनिधानकर्ता का नाम :

(पहला धारक)

विनिधानकर्ता का पता :

स्थायी खाता सं. (पैन) :

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि*

(क) मेरा कोई डीमेट खाता नहीं है और मेरा कोई व्युत्पन्न व्यापार नहीं है ।

(ख) मेरा डीमेट खाता सं. भागीदारी निक्षेपागार.....में है किंतु मैंने इस खाते से कोई साधारण शेयर या व्युत्पन्न नहीं किया है ।

(ग) मेरा संयुक्त डीमेट खाता सं. भागीदारी निक्षेपागारमें है किंतु मैं पहला खाताधारक नहीं हूँ ।

2. मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने राजीव गांधी साधारण बचत स्कीम के सभी निबंधनों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है ।

3. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं राजीव गांधी साधारण बचत स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए नए फुटकर विनिधानकर्ता के रूप में पात्र हूँ ।

4. मैं स्कीम के अधीन सभी अपेक्षाओं और सभी दायित्वों को पूर्ण करने और स्कीम के सभी शर्तों और निबंधनों का पालन करने का वचन देता हूँ।

5. मैं यह समझता हूँ कि स्कीम में विनिर्दिष्ट किसी शर्त का पालन करने में असफल रहने की दशा में, मेरे द्वारा इसके अधीन प्राप्त किए गए लाभ वापस ले लिए जाएंगे और कर मेरे द्वारा तदनुसार देय होंगे।

विनिधानकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

* जो उपयुक्त हो उसे सही करें।

प्ररूप ख

[पैरा 6 (ग) और (घ) देखें]

नए फुटकर विनिधानकर्ता द्वारा पात्र प्रतिभूतियों के क्रय पर भागीदार निक्षेपागार को प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा।

सेवा में

भागीदार निक्षेपागार

पता

यह सूचना दी जाती है कि मेश डीमेट खाता सं. भागीदार निक्षेपागार.....में है और निम्नलिखित प्रतिभूतियां

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

मेरे पास है।

(ङ) उपर्युक्त डीमेट खाते में को क्रय की गई राजीव गांधी साधारण बचत स्कीम के प्रयोजनों के लिए विनिधान के रूप में सम्मिलित नहीं होंगी।

हस्ताक्षर

विनिधानकर्ता का नाम :

(पहला धारक)

विनिधानकर्ता का पता :

स्थायी खाता सं. (पैन) :

प्ररूप ग

[पैरा 10 और 11 देखें]

30 अप्रैल से पूर्व इलैक्ट्रॉनिक रूप विधान में आय-कर विभाग को निक्षेपागार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट

(वित्तीय वर्ष 2012-13 के 80गगछ के लाभ के लिए)

							2012-13 की रिपोर्ट 30 अप्रैल 2013 को देनी होगी	2013-14 की रिपोर्ट 30 अप्रैल 2014 को देनी होगी	2014-15 की रिपोर्ट 30 अप्रैल 2015 को देनी होगी	2015-16 की रिपोर्ट 30 अप्रैल 2016 को देनी होगी
नाम	पैन	डीमेट खाता सं.	खाता खोलने की तारीख	रोक के प्रयोजनों के लिए विनिधान की तारीख (रागसा बस्की # में पात्र स्क्रिप में अंतिम विनिधान करने की तारीख	विनिधान की राशि	रागसा बस्की # में रोकी गई स्क्रिप	क्या रागसा बस्की# के अधीन खाता पात्र है	क्या रागसाबस्की # के साथ संकलित खाता है नियत रोक अवधि*	क्या रागसाबस्की # के साथ संकलित खाता है 270 दिनों के संबंध में*	क्या रागसाबस्की # के साथ संकलित खाता है 270 दिनों के संबंध में*

*31 मार्च 2013 तक आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप विधान अवधारित किया जाएगा ।

**प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष एक वित्तीय वर्ष द्वारा बढ़ाया गया ।

आरजीई एसएस से राजीव गांधी साधारण बचत स्कीम अभिप्रेत है ।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd November , 2012

(Income-Tax)

S.O. 2777(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 80CCG of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

1. **Short title, commencement and application.** - (1) This Scheme may be called the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme, 2012.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
 - (3) This Scheme shall apply for claiming deduction in the computation of total income of the assessment year relevant to a previous year on account of investment in eligible securities under sub-section (1) of section 80CCG of the Income-tax Act, 1961.
2. **Objective of Scheme.**—The objective of the Scheme is to encourage the savings of the small investors in domestic capital market.
3. **Definitions.**— In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
 - (i) "Act" means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
 - (ii) "demat account" means an account opened with the depository participant in accordance with the guidelines laid down by the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
 - (iii) "depository" means a company as defined in clause (e) of sub-section (1) of section 2 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996);
 - (iv) "depository participant" means a participant as defined in clause (g) of sub-section (1) of section 2 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996);
 - (v) "eligible securities" means any of the following :-
 - (a) equity shares, on the day of purchase, falling in the list of equity declared as "BSE-100" or "CNX-100" by the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange, as the case may be;

4391 GI/12-3

- (b) equity shares of public sector enterprises which are categorised as Maharatna, Navratna or Miniratna by the Central Government;
- (c) Units of Exchange Traded Funds (ETFs) or Mutual Fund (MF) schemes with Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme (RGESS) eligible securities as underlying, as mentioned in sub-clause (i) or sub-clause (ii) above, provided they are listed and traded on a stock exchange and settled through a depository mechanism;
- (d) Follow on Public Offer of sub-clauses (i) and (ii) above;
- (e) New Fund Offers (NFOs) of sub-clause (iii) above;
- (f) Initial Public Offer of a public sector undertaking wherein the government shareholding is at least fifty-one per cent. which is scheduled for getting listed in the relevant previous year and whose annual turnover is not less than four thousand crore rupees during each of the preceding three years;
- (vi) "financial year" means a year commencing on the 1st day of April and ending on the 31st day of March;
- (vii) "Form" means the Form appended to the Scheme;
- (viii) "investment" means investment by an assessee in any of the eligible securities in accordance with the Scheme;
- (ix) "new retail investor" means the following resident individuals:-
 - (a) any individual who has not opened a demat account and has not made any transactions in the derivative segment as on the date of notification of the Scheme;
 - (b) any individual who has opened a demat account before the notification of the Scheme but has not made any transactions in the equity segment or the derivative segment till the date of notification of the Scheme,

and any individual who is not the first account holder of an existing joint demat account shall be deemed to have not opened a demat account for the purposes of this Scheme
- (x) "Scheme" means the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme;
- (xi) words and expressions used and not defined in this Scheme, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. **Eligibility .-** The deduction under the Scheme shall be available to a new retail investor who complies with the conditions of the Scheme and whose gross total income for the financial year in which the investment is made under the Scheme is less than or equal to ten lakh rupees.

5. **Procedure at time of opening demat account.**—The new retail investor shall follow the following procedure at the time of opening or designating a demat account :-
- (a) the new retail investor shall open a new demat account or designate his existing demat account for the purpose of availing the benefit under the Scheme;
 - (b) the new retail investor shall submit a declaration in Form A to the depository participant who will forward the same to the depository for verifying the status of the new retail investor;
 - (c) the new retail investor shall furnish his Permanent Account Number (PAN) while opening the demat account or designating the existing account as a Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme eligible account, as the case may be.
6. **Procedure for investment under Scheme.**— A new retail investor shall make investments under the Scheme in the following manner :-
- (a) the new retail investor may make investment in eligible securities in one or more than one transactions during the year in which the deduction has to be claimed;
 - (b) the new retail investor may make any amount of investment in the demat account but the amount eligible for deduction, under the Scheme shall not exceed fifty thousand rupees;
 - (c) the eligible securities brought into the demat account, as declared or designated by the new retail investor, will automatically be subject to lock-in during its first year, as per the provisions of paragraph 7, unless the new retail investor specifies otherwise and for such specification, the new retail investor shall submit a declaration in Form B indicating that such securities are not to be included within the above limit of investment;
 - (d) the new retail investor shall be eligible for a deduction under sub-section (1) of section 80CCG of the Act in respect of the actual amount invested in eligible securities, in the first financial year in respect of which a

declaration in Form B has not been made, subject to the maximum investment limit of fifty thousand rupees;

(e) the new retail investor who has claimed a deduction under sub-section (1) of section 80CCG of the Act, in any assessment year, shall not be allowed any deduction under the Scheme for any subsequent assessment year;

(f) the new retail investor shall be permitted a grace period of three trading days from the end of the financial year so that the eligible securities purchased on the last trading day of the financial year also get credited in the demat account and such securities shall be deemed to have been purchased in the financial year itself;

(g) the new retail investor may also keep securities other than the eligible securities covered under the Scheme in the demat account through which benefits under the Scheme are availed;

(h) the new retail investor can make investments in securities other than the eligible securities covered under the Scheme and such investments shall not be subject to the conditions of the Scheme nor shall they be counted for availing the benefit under the Scheme;

(i) the investment under the Scheme shall consist of all eligible securities covered under the Scheme that are initially bought by the investor under the Scheme or that are bought subsequently by the investor as per the provisions of the Scheme;

(j) the deduction claimed shall be withdrawn if the lock-in period requirements of the investment are not complied with or any other condition of the Scheme is violated.

7. **Period of holding requirements.** - (1) The period of holding of eligible securities shall be three years to be counted in the manner detailed hereunder.

(2) All eligible securities are required to be held for a period called the fixed lock-in period which shall commence from the date of purchase of such securities in the relevant financial year and end one year from the date of

purchase of the last set of eligible securities (in the same financial year) on which deduction is claimed under the Scheme.

(3) The new retail investor shall not be permitted to sell, pledge or hypothecate any eligible security during the fixed lock-in period.

(4) The period of two years beginning immediately after the end of the fixed lock-in period shall be called the flexible lock-in period.

(5) The new retail investor shall be permitted to trade the eligible securities after the completion of the fixed lock-in period subject to the following conditions:-

(a) the new retail investor shall ensure that the demat account under the Scheme is compliant for a cumulative period of a minimum of two hundred and seventy days during each of the two years of the flexible lock-in period as laid down hereunder:-

(A) the demat account shall be considered compliant for the number of days where value of the investment portfolio of eligible securities, within the flexible lock-in period, is equal to or higher than the amount claimed as investment for the purposes of deduction under section 80CCG of the Act;

(B) in case the value of investment portfolio in the demat account falls due to fall in the market rate of eligible securities in the flexible lock-in period, then notwithstanding sub clause(A), -

(i) the demat account shall be considered compliant from the first day of the flexible lock-in period to the day any such eligible securities are sold during this period;

(ii) where the assessee sells the eligible securities mentioned in sub-clause (B) from his demat account, he shall have to purchase eligible securities and the said demat account shall be compliant from the day on which the value of the investment portfolio in the account becomes -

4391 GI/12-4

(I) at least equivalent to the investment claimed as eligible for deduction under section 80CCG of the Act or;

(II) the value of the investment portfolio under the Scheme before such sale,

whichever is less.

(6) The new retail investor's demat account created under the Scheme shall, on the expiry of the period of holding of the investment, be converted automatically into an ordinary demat account.

(7) For the purpose of valuation of investment during the flexible lock-in period, the closing price as on the previous day of the date of trading, shall be considered.

(8) While making the initial investments upto fifty thousand rupees, the total cost of acquisition of eligible securities shall not include brokerage charges, Securities Transaction Tax, stamp duty, service tax and all taxes, which are appearing in the contract note.

(9) Where the investment of the new retail investor undergoes a change as a result of involuntary corporate actions like demerger of companies, amalgamation, etc. resulting in debit or credit of securities covered under the Scheme, the deduction claimed by such investor shall not be affected.

(10) In case of voluntary corporate actions like buy-back, etc. resulting only in debit of securities, where new retail investor has the option to exercise his choice, the same shall be considered as a sale transaction for the purpose of the Scheme.

(11) The Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) shall notify the corporate actions, referred to in sub-paragraph (9), allowed under the Scheme in this regard.

8. If the new retail investor fails to fulfil any of the provisions of the Scheme, the deduction originally allowed to him under sub-section (1) of section 80CCG of the Act for any previous year, shall be deemed to be the income of the assessee of such previous year and shall be liable to tax for the assessment year relevant to such previous year.

9. (1) The depository shall certify the new retail investor status of the assessee at the time of designating his demat account as demat account for the purpose of the Scheme.

- (2) The depository participant shall furnish an annual statement of the eligible securities invested in or traded through the demat account to the demat account holder.
10. The depository shall provide a consolidated statement of details in the electronic format, as specified in Form C, on all the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme beneficiaries to the Director General of Income Tax (Systems) or any other person authorised by him, within a period of thirty days from the end of the relevant financial year.
 11. For the purpose of paragraph 10, the Director General of Income Tax (Systems) shall determine the procedures, formats and standards for furnishing of the report in electronic format in Form C by the depositories.
 12. Assesseees shall be liable to submit the relevant records to the income-tax authorities for verification, as and when required.

[Notification No. 51/2012-F.No. 142/35/2012-TPL]

RAMAN CHOPRA, Director (TPL-II)

Form A

[See paragraph 5(b)]

Declaration to be submitted by the investors to the depository participants for availing the benefits under the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme.

Name of the Investor:

(first holder)

Address of the investor:

Permanent Account Number (PAN):

1. It is hereby certified that* ---

(a) I do not have a demat account and I have not traded in any derivatives.

(b) I have demat account no _____ in _____ depository participant but I have not traded in any equity shares or derivatives in this account.

(c) I have a joint demat account no _____ in _____

4391 GI/12-5

_____ depository participant but I am not the first account holder.

2. I hereby declare that I have read and understood all the terms and conditions of the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme.
3. It is hereby verified that I am an eligible new retail investor for availing the benefits under the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme.
4. I undertake to abide by all the requirements and fulfill all obligations under the Scheme, and will comply with all the terms and conditions of the Scheme.
5. I understand that, in case I fail to comply with any condition specified in the Scheme, the benefits availed there under will be withdrawn and the tax shall be payable by me accordingly.

Signature of the Investor

Place:

Date:

* Tick which ever is appropriate.

Form B

[See paragraph 6(c) and (d)]

Declaration to be submitted by the new retail investor to the depository participant on purchase of eligible securities.

To

Depository participant

Address

It is hereby informed that I have demat account no _____ in _____ depository participant and the following securities

(a)

(b)

(c)

(d)

- (e) purchased in the aforesaid demat account on _____ are not to be included as investment for the purpose of the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme.

Signature

Name of the Investor:

(first holder)

Address of the investor:

Permanent Account Number (PAN):

Form C**[See paragraphs 10 and 11]**

Annual report to be submitted by the depository to the Income Tax Department in Electronic Format before 30th April.

(For 80 CCG benefits of Financial Year 2012-13)

							2012-13 Report to be furnished by 30 th April 2013	2013-14 Report to be furnished by 30 th April 2014	2014-15 Report to be furnished by 30 th April 2015	2015-16 Report to be furnished by 30 th April 2016
Name	PAN	DEMAT A/c No.	Date of opening A/c	Date of investment for the Purpose of lock-in (date of making the last investment in RGESS# eligible scrip)	Amount of Investment	Scripts locked in RGESS#	Whether A/c eligible under the RGESS# Scheme	Whether A/c compliant with RGESS# with respect to fixed lock-in*	Whether A/c compliant with RGESS# with respect to 270 days period*	Whether A/c compliant with RGESS# with respect to 270 days period*

* The Electronic Format shall be determined by the Director General of Income Tax (Systems) by 31st March, 2013.

**The Financial Year shall be enhanced by one Financial Year every year.

#RGESS means the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme.